

# संकट से आत्मविश्वास तक भारत की यात्रा\*

शक्तिकान्त दास

‘विश्व आर्थिक मंच’ की वार्षिक बैठक के लिए दावोस में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि बाहर सर्दी है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित मान्यवरों और विशेषज्ञों के एक साथ आने से वातावरण में गर्माहट पैदा हुई है जिससे यह सर्दी महसूस नहीं होती। इस तरह की बैठकें तब अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं जब संभावित रूप से हमारे साझा भविष्य को आकार देने वाले मूलभूत परिवर्तन वैश्विक स्तर पर हो रहे हों। इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए मैं ‘भारतीय उद्योग परिसंघ’ (सीआईआई) को धन्यवाद देता हूँ।

वैश्विक समष्टि-आर्थिक मोर्चे पर हालिया जानकारी कुछ हद तक आश्चर्य करने वाली रही है क्योंकि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के करीब आ रही है, और संवृद्धि भी उम्मीद से बेहतर रही है। सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना बढ़ गई है और इससे वित्तीय बाजार उत्साहित हैं। वित्तीय स्थितियाँ दबावमुक्त हैं, और बाजार नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन यह चिंता बढ़ गई है कि वे खुद समय से आगे न निकल जाएं। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कुछ कठिन तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि - वैश्विक संवृद्धि धीमी हो रही है; नई प्रतिकूल घटनाओं और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के डर से भू-राजनीतिक स्थिति नाजुक बनी हुई है; भू-आर्थिक विखंडन लगातार बना हुआ है जिससे वैश्विक व्यापार कमजोर हो रहा है; और जलवायु संबंधी कठिन चुनौतियाँ अपना प्रभाव जमा रही हैं।

इस वैश्विक परिवेश को भूमिका में रखते हुए मैं मुख्य रूप से भारत की संकट से आत्मविश्वास तक की यात्रा के बारे में बात करूंगा। मैं सबसे पहले व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में हमारे हालिया अनुभव का जिक्र करूंगा, जो एक

\* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 जनवरी 2024 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया भाषण।

केंद्रीय बैंक की प्रमुख जिम्मेदारी है। फिर मैं उभरते फिनटेक वातावरण और भुगतान पारितंत्र के बारे में बात करूंगा जो वित्तीय नवाचार और समावेशन में भारत की सफलता की पहचान बन गए हैं। अंत में कुछ समापन टिप्पणियां होंगी।

## समष्टि आर्थिक स्थिरता

वैश्विक स्तर पर अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक माहौल के रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आशावाद की तस्वीर पेश करती है। संवृद्धि संबंधी हाल के परिणाम अधिकांश पूर्वानुमानों से आगे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की नवीनतम जानकारी के अनुसार 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद 2023-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत के साथ वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू मांग मजबूत बनी रहने के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अब वह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में देखें तो भारत पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया है कि विश्व संवृद्धि में भारत का योगदान मौजूदा 16 प्रतिशत से बढ़कर 2028 तक 18 प्रतिशत हो जाएगा। मजबूत घरेलू मांग संवृद्धि का मुख्य चालक बनी हुई है। तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व के साथ जुड़ाव में व्यापार और वित्तीय मार्गों के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घरेलू मांग पर अधिक निर्भरता ने भारत को कई बाहरी संकटों से बचाया है।

मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के बल पर हम हालिया आघातों से उबरे हैं - मुद्रास्फीति कम हो रही है; बैंक और कॉरपोरेट के तुलन-पत्र पहले से अधिक मजबूत हैं; राजकोषीय सुदृढ़ता जारी है और उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है; और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के साथ बाहरी संतुलन पूरी तरह नियंत्रण में है। उचित नीति दर और चलनिधि उपायों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की निर्णायक और समय पर मौद्रिक नीति कार्रवाइयों ने भारत की त्वरित और स्थिर बहाली में मदद की। इसके अलावा कराधान, बैंकिंग, व्यापार करने में आसानी, विनिर्माण,

मुद्रास्फीति प्रबंधन, डिजिटलीकरण के साथ-साथ भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर स्पष्ट ध्यान देने के क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की मध्यम और दीर्घावधि संवृद्धि क्षमता को बढ़ावा दिया है। ये सुधार भारतीय व्यवसायों को उत्पादकता में सुधार करने और सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तनों को अपनाने में लगातार मदद कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के समर्थन से एक उल्लेखनीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है।<sup>1</sup> सेवा क्षेत्र, जिसका अर्थव्यवस्था के कुल मूल्यवर्धन में सबसे बड़ा हिस्सा है, वितरण, पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए तेजी से नई प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण भारत की सेवाओं की बाहरी मांग बढ़ रही है और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के अलावा व्यवसाय विकास, अनुसंधान और विकास, पेशेवर प्रबंधन, लेखा और कानूनी सेवाओं जैसी अन्य पेशेवर सेवाओं तक तेजी से और विविधतापूर्ण हो रही है।

हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो 2022 की गर्मियों में अपने अत्यधिक ऊंचे स्तर पर थी, काफी हद तक कम हो गई है। यह अवस्फीति सीपीआई कोर (खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर) मुद्रास्फीति में लगातार कमी आने के कारण है। मुख्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव कम हो रहा है। इससे पता चलता है कि चलनिधि के पुनर्संतुलन के साथ-साथ मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की हमारी मौद्रिक नीति कार्रवाई काम कर रही है। वस्तुओं की ऊंची कीमतों और आपूर्ति पक्ष के आघातों से प्रेरित कॉस्ट-पुश दबाव भले ही कम हो गया है, प्रतिकूल अस्थायी खाद्य मूल्य आघात अपनी बढ़ती घटनाओं और तीव्रता के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति में काफी अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार के आपूर्ति पक्ष में सक्रिय हस्तक्षेप ने खाद्य कीमतों के आघातों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे की सोचें तो खाद्य कीमतों में अनिश्चितता बनी रहने के कारण मुद्रास्फीतिक

दृष्टिकोण काफी प्रभावित होगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बार-बार लगने वाले आघातों से मुद्रास्फीति की उम्मीदें अपेक्षाओं के परे जा सकती हैं और कीमतों का दबाव एक सामान्य बात बन सकती है। इन अनिश्चितताओं के बीच, मौद्रिक नीति को सतर्क रहने और मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर की ओर ले जाने के लिए सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी बने रहने की आवश्यकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्थिर मुद्रास्फीति भारत की संवृद्धि महत्वाकांक्षाओं को आधार प्रदान करेगी।

अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि संभावना की बात करें तो हमारे शोध दल हमारी आगामी फरवरी 2024 की मौद्रिक नीति के लिए एक व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं। वर्तमान स्तर पर, हमारी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। जहां तक संवृद्धि का सवाल है, मेरा मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। मैं यह बात भारत में हो रही मजबूत आर्थिक गतिविधियों की गति के आधार पर कह रहा हूँ। कुल मिला कर वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होकर लगातार चार वर्षों तक संवृद्धि 7 प्रतिशत और उससे अधिक रहेगी।

### वित्तीय स्थिरता

अब मैं वित्तीय स्थिरता की बात करूंगा। मौद्रिक स्थिरता की सुरक्षा; अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति; जमाकर्ताओं और निवेशकों के हितों की रक्षा; और टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि हासिल करने के लिए एक स्थिर और कुशल वित्तीय प्रणाली का होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि बैंकिंग क्षेत्र की आय मजबूत है, बफर मजबूत है, अभिशासन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हुआ है और तुलन-पत्र मजबूत हुए हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई व्यापक, विवेकपूर्ण और सक्रिय वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के तहत बैंकों के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। कुल मिलाकर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हाल की अवधि में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। रिजर्व बैंक का ध्यान केवल विनियामक मापदंडों के अनुपालन पर नहीं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली की आंतरिक सुरक्षा को वास्तविक रूप से मजबूत

<sup>1</sup> एनएसओ द्वारा जारी 2023-24 के प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के आधार पर, विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 17.7 प्रतिशत है, जबकि सेवा क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 63.3 प्रतिशत है।

करने पर है, जिसने हमें अच्छी स्थिति में खड़ा किया है, जो कि नवीनतम प्रदर्शन संकेतकों से देखा जा सकता है।<sup>2</sup>

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र भी अच्छे प्रदर्शन मापदंडों को प्रतिबिंबित कर रहा है।<sup>3</sup> वित्तीय संस्थाओं के बेहतर तुलन-पत्र टिकाऊ और व्यापक आधार वाली ऋण संवृद्धि को अच्छा समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के तहत बैंकों की समुत्थानशीलता का आकलन करने के लिए किए गए मैक्रो स्ट्रेस परीक्षणों से पता चलता है कि उनका पूंजी अनुपात विनियामक न्यूनतम<sup>4</sup> से पर्याप्त रूप में ऊपर रहेगा। हालांकि, खुदरा ऋण, विशेष रूप से असुरक्षित ऋण में तेज वृद्धि और बैंकों और एनबीएफसी के बीच बढ़ती अंतर-संबद्धता के कारण जोखिमों के संभावित निर्माण को रोकने और वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक को पूर्वापाय के रूप में नीतिगत कार्रवाई करना जरूरी हुआ है।<sup>5</sup>

कुछ उन्नत देशों की बैंकिंग प्रणाली में हाल के घटनाक्रमों के चलते विवेकपूर्ण आर्स्ति देयता प्रबंधन; सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन; देयता और आर्स्ति में टिकाऊ संवृद्धि; समय-समय पर दबाव परीक्षण का आयोजन; और भविष्य के किसी भी अप्रत्याशित दबाव के लिए पूंजी बफर निर्माण सुनिश्चित करने के महत्व पर बल

<sup>2</sup> बैंकिंग प्रणाली का पूंजी-जोखिम भारित आर्स्ति अनुपात (सीआरएआर) 16.8 प्रतिशत पर विनियामक न्यूनतम से काफी ऊपर बना हुआ है, जबकि लाभप्रदता बहु-दशकीय ऊंचाई पर पहुंच गई है। बैंकिंग प्रणाली का आर्स्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 13.7 प्रतिशत है। सकल अनर्जक आर्स्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आर्स्ति (एनएनपीए) अनुपात क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत के कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने से आर्स्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है।

<sup>3</sup> सितंबर 2023 में एनबीएफसी का सीआरएआर 27.6 प्रतिशत पर विनियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत से काफी ऊपर बना हुआ है; जीएनपीए अनुपात दिसंबर 2021 में 7.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर सितंबर 2023 में 4.3 प्रतिशत हो गया है; और सितंबर 2023 में एनआईएम और आरओए क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत थे।

<sup>4</sup> उदाहरण के लिए आय वक्र में यदि 250 आधार अंक (मई 2022-फरवरी 2023 के बीच संघटी दर वृद्धि) को समानांतर अपवर्ड शिफ्ट के रूप में लागू किया जाता है, तो बैंकों के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो पर मार्क-टू-मार्केट प्रभाव के कारण सितंबर 2023 में प्रणाली स्तर का पूंजी-जोखिम भारित आर्स्ति अनुपात (सीआरएआर) 16.6 प्रतिशत से घटकर 13.1 प्रतिशत हो जाएगा। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर इसी तरह के आघात से सीआरएआर घट कर 15.6 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, दोनों मामलों में, सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से ऊपर रहेगा।

<sup>5</sup> खुदरा ऋण के कुछ क्षेत्रों में लगातार ऋण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर 2023 को अवांछित अत्यधिकता को कम करने के लिए पूर्वापायों की घोषणा की गई थी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उपभोक्ता ऋण के कुछ खंडों पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया गया। एनबीएफसी को बैंक ऋण के माध्यम से परस्पर जुड़ाव के मुद्दे को भी उच्च जोखिम भार के माध्यम से ठीक किया गया है।

दिया गया है।<sup>6</sup> रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और वास्तविक अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को सहारा देने के लिए सूक्ष्म और वृहत विवेकपूर्ण, ऐसे मिले-जुले उचित उपायों को लागू किया है।<sup>7</sup>

रिजर्व बैंक ने बैंकों, एनबीएफसी, शहरी सहकारी बैंकों और वित्तीय पारितंत्र के अन्य क्षेत्रों के विनियामक ढांचे में बदलाव किया है। साइबर सुरक्षा जोखिमों को कम करने और विनियमित संस्थाओं की परिचालनगत समुत्थानशीलता को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि नवाचार को गैर-विघटनकारी तरीके से वित्तीय प्रणाली में समाहित किया जाए और साथ ही उचित ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा हमने रिजर्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कमजोरियों के मूल कारणों की पहचान करके और ऐसे कारकों के संकट में बदलने से पहले समय पर कार्रवाई शुरू करके जोखिम कारकों की शीघ्र पहचान और निराकरण की ओर जोर दिया गया है। प्रणाली को अधिक सक्रिय और दूरदर्शी होने और संकट को पहले से भांपने के लिए पुनः व्यवस्थित किया गया है।

वित्तीय स्थिरता का एक प्रमुख घटक ऐसी मुद्रा का होना है जो स्थिर हो और जिसमें परिस्थिति के अनुरूप मूल्यवर्धन या मूल्यहास होता हो। स्थिर मुद्रा का लाभ व्यवसायों, निवेशकों और सबसे बढ़कर लोगों सहित अर्थव्यवस्था में विभिन्न हितधारकों को होता है। अत्यधिक अस्थिरता होने पर केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार हस्तक्षेप करके उसे रोका जाना चाहिए, विशेष रूप से उभरती

<sup>6</sup> भारत में जोखिम प्रबंधन उपाय मौजूद हैं जिसके तहत बैंक ब्याज दर चक्र के बढ़ने के साथ ब्याज दर जोखिम के लिए प्रावधान कर सकते हैं। निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) का पर्याप्त स्तर बैंकों के लिए आवश्यक बफर निर्मित करता है। इसके तहत बैंक निवेश की बिक्री पर निवल लाभ अंतरित करते हैं जब तक कि यह ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो के कम से कम 2 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता है। इसके अलावा, भारत में सभी वाणिज्यिक बैंक, भले ही उनका आकार कुछ भी हो, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) दिशानिर्देशों के अधीन हैं, जिनमें असुरक्षित थोक वित्तपोषण के लिए कठोर प्रक्रिया है। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के निवेश पर मूल्यांकन दिशानिर्देश सख्त हैं और इस संबंध में रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

<sup>7</sup> हमने बड़े एक्सपोजर प्रेमवर्क, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पैमाना-आधारित विनियमन और पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए डिजिटल ऋण मानदंडों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हम कभी-कभार सामने आने वाले जोखिमों के निराकरण के लिए लचीले ढंग से व्यापक विवेकपूर्ण साधनों के रूप में क्षेत्र विशिष्ट जोखिम भार, प्रावधान मानदंड, ऋण-मूल्य अनुपात जैसे अन्य पारंपरिक उपायों का भी उपयोग करते हैं।

बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) में यह जरूरी है। भारतीय रुपया एक स्वतंत्र रूप से मूल्य धारण करने वाली मुद्रा है और इसकी विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। हाल की अवधि में इसकी सापेक्ष स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत, उसके समष्टि आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और भारत की बाहरी स्थिति में सुधार, विशेष रूप से चालू खाता घाटे (सीएडी) में महत्वपूर्ण कमी और अनुकूल विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति के कारण पूंजी प्रवाह के पुनरुद्धार का परिणाम है। विश्लेषण के लिए समय अवधि चुनकर भारतीय रुपये का किसी अन्य तरीके से उल्लेख करना न तो उचित है और न ही वास्तविकता के साथ संगत है।

बढ़ती अनिश्चितता की हालिया अवधि के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) अमेरिकी डॉलर और बांड प्रतिफल में अत्यधिक अस्थिरता के दौर में थीं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रणालीगत महत्व को देखते हुए, इन उतार-चढ़ाव से होने वाला प्रभाव अप्रत्याशित नहीं है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका में मौद्रिक नीति रुख और उसके स्वयं के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में अपेक्षाएं बदल रही हों। ऐसी स्थिति में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं, जिनकी अपनी घरेलू उलझनें और चुनौतियाँ हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय चक्रों द्वारा प्रभावित होने का जोखिम नहीं उठा सकतीं। इन अर्थव्यवस्थाओं को अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करना होगा। हम इस बात से सहमत हैं कि विनिमय दरों में लचीलापन होना चाहिए, लेकिन उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका अस्थिर कर देने वाला प्रभाव नहीं होना चाहिए। तदनुसार, बहुपक्षीय संस्थानों के लिए ईएमई के नीतिगत परिप्रेक्ष्य पर अधिक सूक्ष्म और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना अच्छा रहेगा।

कुल मिलाकर, भारत में घरेलू व्यापक आर्थिक और प्रणालीगत जोखिमों में गिरावट आई है और विनियामकों की विवेकपूर्ण नीतियों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के तुलन-पत्रों में सुधार ने वित्तीय प्रणाली की समुत्थानशीलता को मजबूत किया है।

### फिनटेक और भुगतान पारितंत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था के कई पहलू हैं जो बहुत सारी संभावनाओं को दर्शाते हैं। मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और वह है फिनटेक और भुगतान पारितंत्र।

भारत में फिनटेक पारितंत्र ने वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता, कुशल और अधिक सुलभ बनाकर उनके वितरण में काफी सुधार किया है। भारत में कार्यरत फिनटेक संस्थाओं की संख्या के संदर्भ में भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारितंत्र है। भारत में फिनटेक को अपनाने की दर 87 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 67 प्रतिशत से काफी ऊपर है। भारत का फिनटेक बाजार 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021 के 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।<sup>8</sup> जेएएम ट्रिनिटी जो बैंक खातों (जन धन); आधार (भारत की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जो पहचान का एकल और पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करती है); और मोबाइल फोन नंबर का एक संयोजन है, ने वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण और समग्र सेवा वितरण के मामले में भारत के फिनटेक पारितंत्र में क्रांति ला दी है।

स्वदेशी रूप से विकसित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसकी सफलता की कहानी वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन गई है। सभी बैंकों में यूपीआई अंतरसंचलन ने एक एकीकृत भुगतान पारितंत्र निर्माण किया है। इसके यूजर-अनुकूल इंटरफेस और क्यूआर कोड-आधारित भुगतान ने इसे बहुत लोकप्रिय बना दिया है। इसने छोटे व्यवसायों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है। दिसंबर 2023 में यूपीआई के माध्यम से किए गए 12 बिलियन से अधिक लेनदेन से इसकी सफलता दिखाई देती है। यूपीआई में हाल ही में जोड़ी गई सुविधाओं, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रणाली द्वारा समर्थित 'कन्वर्सेशनल पेमेंट्स'; ऑफलाइन लेनदेन; और क्रेडिट लाइनों को यूपीआई से जोड़ने से इसकी बहुउपयोगिता में और वृद्धि होगी। साथ ही साथ 'यूपीआई वन वर्ल्ड' भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा देता है। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे-नाऊ के बीच संबंध स्थापन यूपीआई के संभावित वैश्विक तेज भुगतान प्रणाली के रूप में उसके उत्कृष्ट होने का प्रमाण है। इस तरह के और भी प्रयास जारी हैं। हमने यूपीआई से प्राप्त होने वाली सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

<sup>8</sup> <https://www.investindia.gov.in/sector/bfsi-FinTech-financial-services>.

रिज़र्व बैंक खुदरा और बड़े मूल्य भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे संचालित करता है जिससे भारत रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के साथ चौबीसों घंटे ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाले चुनिंदा देशों के एक समूह का हिस्सा बन गया है। इस प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 485 मिलियन से अधिक डिजिटल भुगतान होते हैं। डिजिटल भुगतान की यह अभूतपूर्व वृद्धि रिज़र्व बैंक के समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक में परिलक्षित होती है जो पिछले 5 वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ गई है।<sup>9</sup>

रिज़र्व बैंक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य पहलें की हैं। 2019 में नवाचार के रूप में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क शुरू किया गया। यह एक सीमित वातावरण में वित्तीय उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण की सुविधा देता है। इसकी उल्लेखनीय सफलताओं में से एक UPI123Pay है, जो ऑफ़लाइन यूपीआई भुगतान की सुविधा देता है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क को 2023 में कई विनियामकों के बीच इंटरऑपरेबल बना दिया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक ग्लोबल हैकथॉन, हारबिंगर, और रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित 'इनोवेशन हब' नवाचार को प्रोत्साहन देने में निजी क्षेत्र के साथ हमारे सहयोगात्मक प्रयासों को और बढ़ाता है।

डिजिटलीकरण की दिशा में एक अगले कदम के रूप में हमारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी), ई-रुपया के लिए नवंबर-दिसंबर 2022 में थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में एक प्रायोगिक प्रयास शुरू किया गया था। तब से 4 मिलियन ग्राहक इसमें जुड़ चुके हैं। सीबीडीसी डिजिटल लेनदेन को बढ़ाएगा,

खासकर उन क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट सुविधा सीमित है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सीबीडीसी (ई-रुपया) एक वैश्विक मानदंड बन जाएगा और निर्बाध सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।

फिनटेक पारितंत्र के क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण ग्राहक-केंद्रित है, जिसमें प्रभावी निरीक्षण, नैतिक आचरण, और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना करके फिनटेक द्वारा स्वयं-विनियामन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

### निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सभी हितधारकों और वैश्विक एजेंसियों द्वारा सामूहिक और समन्वित कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि दावोस चर्चा सहयोग की भावना को सक्रिय करेगी और हमें बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन करेगी।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, वह अब दीर्घावधि में उच्च संवृद्धि के लिए तैयार है। चुनौतियाँ हैं, लेकिन उनसे प्रभावी ढंग से निपटना होगा। कई अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारत की संभावनाओं पर विश्वास अब तक के उच्चतम स्तर पर है। हमें इसे वास्तविकता में रूपांतरित करना है। सभी हितधारकों को चाहिए कि वे इस ओर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए इस यात्रा का समर्थन करने के लिए उपाय करें हैं।

धन्यवाद ! नमस्कार !

<sup>9</sup> आरबीआई का समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2018 के 100 से बढ़कर मार्च 2023 में 395.6 हो गया है।